[Shri S. N. Mishra.]

The Additional Commissioner of Railway Safety, Calcutta, has commenced his statutory enquiry into the accident.

MOTION RE FOOD SITUATION—continued.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस खाद्य समस्या के विवाद के प्रारम्भ में हमारे मित्र माननीय श्री गुरुपाद स्वामी जी ने कुछ सवाल उठाये और मुझे आश्चर्य है कि कुछ समाजवादी साथियों ने और हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त ने भी इन बातों को उचित नहीं समझा। श्री गुरुपाद स्वामी जी ने कहा था कि किसी भी पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था वाले देश में अगर विकास करना है तो उसमें शुरू में कुछ कठिनाइयां होती हैं और उन कठिनाइयों का मुकाबला भी करना पड़ता है तथा विकास के साथ ही साथ कीमतें भी कुछ बढ़ती हैं। मैं नहीं समझता कि अर्थ शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए यह एक ऐसी बात होगी जिसके बारे में कोई विवाद हो। हर आदमी जानता है कि पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था से विकास की ओर जाने में जो विकास के काम होते हैं, उनके साथ ही साथ कीमत भी बढ़ती है। लेकिन इन कीमतों के बढ़ने से परेशानी तब होती है जब किसी खास क्षेत्र में बहुत ऊंची कीमत हो जाती है और जिसका असर सारे समाज पर और स्वयं विकास के कार्यों पर पड़ता है।

दूसरी बात माननीय गुरुपाद स्वामी जी ने यह कही कि पुराने समाज से नये समाज में आने पर कुछ कठिनाइयां होती हैं और कुछ अव्यवस्था होती है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय प्रो० मुकुट बिहारी लाल जी ने यह कहा कि जो यह समझते हैं कि एक समाज से दूसरे समाज में जाने पर, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में पहुंचने पर अव्यवस्था होती है, उनको शासक दल में रहने का अधिकार नहीं है। राजनैतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं समझता हूं कि जो भी समाजवादी विचारों में आस्था रखता है, जिसने समाजवादी समाज के दृष्टिकोण को समझा है, वह समझता है कि एक समाज से दूसरे समाज की ओर जाने में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं और इन कठिनाइयों को जाने बिना कोई भी समाज प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है।

आज हमारे मुल्क में जो खाद्य समस्या है उसको दो तीन दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक तो खाद्य समस्या हमारे देश के लिए नई नहीं है, हर साल कुछ क्षेत्रों में अकाल की छाया के रूप में यह समस्या हमारे देश में बनी रहती है। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से लेकर आजादी के आने वाले दिनों में भी हमारे सामने यह परेशानी बराबर उठती रही कि कभी भी देश भुखमरी से तबाह हो सकता है और उसके लिए कुछ उपाय किये जाने चाहियें। श्रीमन्, १९५२–५३ में एक ऐसी हालत पैदा हुई कि इस देश में खाद्यान्नों पर से कंट्रोल उठा लिये गये। अगर हम इसके एक वर्ष पहले और चार वर्ष बाद की परिस्थिति को देखें तो उससे हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार हमारे देश के व्यापारियों ने खाद्य समस्या के साथ खिलवाड़ किया।

सन् १९३० से ही कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि इस मुल्क में खाद्यान्न की कमी है और इसका समाधान यह है कि जो भूमि पर खेती करता है, जो भूमि पर मेहनत करता है, जो जमीन को जोतता है, उसे ही उसका मालिक बनाया जाय। यह बात एक बार नहीं, अनेक बार कही गई है। आजादी आने के बाद भी और आजादी आने के पहले भी। सन् १९३६–३७ में इस बात को फिर से दोहराया गया कि भूमि सुधारों में तेजी लाई जाय। सन् १९४७ के बाद, पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद भी बराबर यह कहा गया है कि भूमि सुधार जितनी जल्दी होंगे उतना ही खेती में उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ

पाया कि रास्ते में कौन सी कठिनाई आ जाती है । आज हमारे देश में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने भूमि सुधार के कामों को अभी तक पूरा नहीं किया । दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब जब खाद्य समस्या के बारे में कोई आयोग या कमिशन बैठा तो उसने भी यही कहा कि भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया जाय । कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रस्तावों में यह कहा कि जमीन का फिर से बंटवारा होना चाहिये और जमीन उनके हाथों में जानी चाहिये जो जमीन पर खेती करते हैं । लेकिन जमीन पर जो स्थिर स्वार्थ के लोग हैं उनका दबाव इस हुकूमत पर पड़ता है, इस नौकरशाही पर जड़ता है जो सारी सरकार की नीतियों को चलाते हैं और इस तरह से भूमि सुधार का काम पूरा नहीं होने पाता ।

इसी तरह से जो सहकारी कृषि की बात कही गई उसका भी हमारे बहुत से मित्र विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जाता है कि यह सवाल पार्टियों की परिधि से बाहर है । लेकिन मैं आपके जरिये से इस सदन से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में जमीन के सवाल का हल सब वर्ग के लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं ।

आज कृषि के क्षेत्र में सहकारिता का विरोध हमारे जो मित्र कर रहे हैं उनका जिक्र मैंने पिछले दिनों जब सहकारिता पर विवाद हो रहा था किया था । मुझे आश्चर्य है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वे कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विरोधी नहीं है लेकिन परसों जब वे विवाद में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने सहकारिता आन्दोलन के बारे में कहा कि हमें इस पर बड़ी सावधानी से नजर रखनी चाहिये और काम करना चाहिये क्योंकि इस मुल्क में सहकारिता आन्दोलन चलने वाला नहीं है । आखिरकार विरोध किस तरह से किया जाता है ? आज जमाने की गति को देखते हुए, समाज की प्रगति को देखते हुए हमारे जनसंघ के मित्र, हमारे स्वतंत्र पार्टी के मित्र सहकारिता आन्दोलन का खुले तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं । लेकिन जिन स्वार्थों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी जड़ में यह निहित है कि सहकारिता आन्दोलन का वे विरोध करें ।

श्रीमन्, हमारे देश में भूमि सुधार नहीं हुआ तो ऐसी हालत में अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा । सरकार की ओर से यह वादा किया गया है कि खाद ज्यादा उत्पादन किया जायेगा और किसानों को खाद दी जायेगी । सरकार के और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक एकड़ जमीन पर, जो सिंचाई की जमीन है, ३० पौंड नाइट्रोजन और १५ पौंड फासफेट्स मिलना चाहिये । इस बारे में बड़े मन्सूबे बांध गये और कहा गया कि किसानों को फर्टिलाइजर दिया जायेगा । मुझे याद है कि एक जमाने में किसानों से यह कहा गया था कि सिन्दरी के कारखाने से खाद दी जायेगी और उस समय सिन्दरी के कारखाने का नाम बड़े फख्र से लिया जाता था और बड़े गर्व के साथ कहा जाता था कि सिन्दरी का कारखाना देश का नक्शा बदल देगा । सिन्दरी के कारखाने के आने से अनाज की समस्या हल हो जायेगी । श्रीमन्, आज से एक महीने पहले मैं आपके साथ सिन्दरी के कारखाने को देखने गया था लेकिन आज हम अभिमान से और उस आवाज से सिन्दरी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं । आज मैं नहीं जानता कि किन कारणों से, सरकार की गलत नीतियों के कारण या जिन अफसरों को वहां पर रखा गया था उनकी वजह से, वह सारे देश के लिए एक कलंक का विषय बन गया है । सिन्दरी के कारखाने से हम लोग जो उम्मीद रखते थे वह नाउम्मीद के रूप में आगे आने वाली है । आज वहां पर केवल नाउम्मीद की ही झलक दिखलाई देती है । आज हमारे देश में जो नई फर्टिलाइजर फैक्टरियां बन रही हैं उनके बारे में भी यही हालत है । श्रीमन्, आप के प्रदेश में एक फर्टिलाइजर

[श्री चन्द्र शेखर]

फैक्टरी बनाने की योजना तीन साल से चल रही है और इसके लिए स्टाफ भी रख दिया गया है जिस पर लाखों रुपया माहवारी खर्च किया जा रहा है। अभी पिछले साल उस फैक्टरी के लिए जमीन एक्वायर की गई। एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि विकास के कार्यों को करने के लिए सीमेन्ट की कमी है लेकिन उस कारखाने में ब्लैक में जितना सीमेन्ट चाहिये आपको मिल सकता है। गोरखपुर और महाराष्ट्र में जो फर्टिलाइजर फैक्टरी बन रही हैं उनकी क्या प्रगति है, उनका कितना विकास आ है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर देश में फर्टिलाइजर का उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में जो काम हो रहा है उसके बारे में जितना कम कहा जाय उतना अच्छा है। इसी तरह से जो सिचाई की योजनाएं बनती हैं उनमें समन्वय नहीं होता है। हम इस सदन सुनते हैं कि जाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हुकूमतें एक साथ नियोजन का काम नहीं करती हैं आप इस बात को सोचें कि इसका नतीजा क्या होता है। एक तरफ तो सिचाई की योजनाएं बरबाद होती जा रही हैं और दूसरी तरफ बाढ़ के पानी से वाटर लागिंग हो जाती है जिससे सारा देश बरबाद हो जाता है।

भूमि सुधार की बात तो अलग है और उसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब एक नया नारा लगाया गया है कि फिर से शिकमी का कानून लागू किया जाय। हम ने सुना है और बड़ी हैरत के साथ सुना है कि हुकूमत इस सम्बन्ध में राय ले रही है विभिन्न प्रदेश सरकारों से कि क्या शिकमी देने का हक फिर से दिया जाय। यह दबाव किन की ओर से पड़ रहा है ? यह दबाव उन लोगों की ओर से पड़ रहा जिन के पास जमीनें हैं। लेकिन जो जमीन के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, वे कह रहे हैं कि उनकी जमीन महफूज रखने के लिये अगर आप यह शिकमी का कानून फिर से जायज नहीं करार देंगे, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्या इस तरह से कोई अर्थव्यवस्था ठीक चल सकती है ? क्या इस तरह से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ सकता है ? मैं आप से निवेदन करूं कि इससे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो भूमि सुधारों को तेजी से करना होगा। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो किसानों को खाद देना होगा। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि में सहकारिता के आन्दोलन को चलाना होगा। आज ७० फी सदी किसान ऐसे हैं जिनके पास एक और दो एकड़ के बीच जमीन है। वे तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिये मिल जुल कर काम करना न सीखें।

इन सारे क्षेत्रों में काम करने के साथ साथ सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रश्न आता है। सामुदायिक विकास मंत्री इस सम्बन्ध में आज जवाब दे रहे थे। एक बार नहीं अनेक बार कहा गया है कि सामुदायिक विकास योजनाएं कृषि के क्षेत्र में काम ठीक तरह से नहीं कर पातीं। सन् १९५७ में जब फूडग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी बनी तो उस फूडग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने कहा कि सामुदायिक विकास योजनाओं से जो उम्मीद थी वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। यह उम्मीद की गई थी कि आने वाले दिनों में ये योजनाए कुछ काम करेंगी। लेकिन आज भी सामुदायिक विकास योजनाएं हमारे सिर पर एक आर्थिक बोझ के रूप में लदी हुई हैं और उनसे कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है।

सन् १९५३ में जब कन्ट्रोल हटाये गये थे तो क्या कहा गया था—सरकार की ओर से कहा गया था कि कंट्रोल की जो बुराइयां हैं, नियंत्रण की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिये धीरे धीरे कंट्रोल को हटायेंगे। लेकिन हमेशा यह खयाल रखेंगे कि व्यापार के ऊपर पूंजीपतियों का एकाधिकार न होने पाये और

स्पेकुलेशन की वजह से, अन्दाज लगाने की वजह से जो जनता को तकलीफ होती है, वह न होने पाये। फिर सन् १९५३ से ले कर सन् १९५६ तक, इन चार वर्षों में धीरे धीरे कंट्रोल हटाये गये और इन वर्षों में अनाज की कीमतें गिरी रहीं। लेकिन सन् १९५६ में ज्यों ही डीकंट्रोल पूरी तरह हो गया, उसके बाद कीमतें बढ़नी शुरू हो गईं। सन् १९५२-५३ में व्यापारियों ने जानबूझ कर कीमतों को कम किया। उस जमाने में एक बड़े जोरों का यह नारा लगाया गया कि कंट्रोल हट जायेंगे, अनियंत्रण हो जायगा, तो समाज में खुशहाली आ जायगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि नियोजित अर्थव्यवस्था में इस तरह से अनियंत्रण की व्यवस्था को चला करके सब से पहली भूल सन् १९५३ में की गई। जब हमारे बफर स्टाक बन रहे थे और जब व्यापार के ऊपर हमारा नियंत्रण चल रहा था, तो उस समय अचानक कंट्रोल को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया और सन् १९५६ से हम फिर स्पेकुलेटर्स के हाथ में खेलने लगे। तब से बराबर यह परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। आज हालत क्या हो रही है? हालत आज यह हो रही है कि यहां पर कहा जाता है कि कंट्रोल मत करो फूडग्रेन्स के ऊपर। हमारे जो नये खाद्य मंत्री हैं, उनसे बड़ी उम्मीद हुई थी जब वे आये। मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें उन्होंने यह कहा था कि अनाज का राज्य व्यापार किया जायगा लेकिन मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में नहीं मालूम इनको क्या मंत्र दे दिया गया जिससे इनकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होने लगी। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बनाने के सम्बन्ध में मुझे यह देख कर हैरानी हुई कि उसका समर्थन कौन करते हैं। उसका समर्थन राजगोपालाचारी जी करते हैं, उसका समर्थन जनसंघ के भाई करते हैं।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया (मध्य प्रदेश) : क्या सही बात कहना गलत है।

श्री चन्द्र शेखर : क्या सही बात ये कहते हैं? जैसा कि माननीय अण्णादुरै जी ने कहा कि इस व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा मान लीजिये ३० फी सदी के ऊपर नियंत्रण रहा और ७० फी सदी पर व्यापारियों का कंट्रोल रहा तो फिर क्या होने वाला है? यह व्यवस्था असफल होने वाली है। उसके बाद यह जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोग कहेंगे कि राज्य व्यापार योजना निकम्मी है, इसको हमेशा के लिये इस हिन्दुस्तान में दफना दिया जाना चाहिये। आप जानते हैं कि ज्यों ही स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बनाने की बात आई, राजगोपालाचारी जी ने अपने ४ अगस्त के "स्वराज्य" अखबार में लिखा कि खाद्य मंत्री साहब वही करने जा रहे हैं जिसको स्वतंत्र पार्टी हमेशा से मानती रही है और जिस का प्रचार करती रही है।

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी (उत्तर प्रदेश) : सरकार ने अपने हाथ में लिये हुए कौन से ट्रेड को अच्छे ढंग से अब तक चलाया है? कोई भी नाम बतायें माननीय सदस्य। (*Interruption*)

श्री चन्द्र शेखर : अगर श्रीमान् जी समय दें तो मैं बता सकता हूं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मैं यह मानता हूं कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि जो आज व्यापारी हैं वे नौकरशाही से ज्यादा भ्रष्ट हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारी योजनाओं में कमियां हैं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि जो व्यापारी आज व्यापार चला रहे हैं, उनमें ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, उनमें ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको समाज की कोई फिक्र नहीं है।

तो ४ अगस्त के "स्वराज्य" में राजा जी ने यह लिखा कि माननीय सुब्रह्मण्यम जी का वे समर्थन करते हैं। उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की बात करके उनके मन की बात कर दी। ७ अगस्त को जनसंघ के अखबार "आर्गेनाइजर" ने लिखा कि वे भी

[श्री चन्द्र शेखर]

इसका समर्थन करते हैं। माननीय सुब्रह्मण्यम् साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। अब आप देखिये कि मुंशी साहब ने स्वतंत्र पार्टी की मीटिंग में खाद्य समस्या पर प्रस्ताव पेश करते वक्त क्या कहा। यह २ अगस्त के अखबार में छपा है। उसमें कहा गया है:

It was a resolution which was moved by Mr. K. M. Munshi, a former Food Minister, opposing the move towards State trading and the imposition of a ceiling on individual land holdings and it said farmers should be allowed to hold bigger and economic holdings to help them increase the production.

(Time bell rings)

श्रीमान्, अभी तो . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : ११ मिनट हो गये।

श्री चन्द्र शेखर : श्रीमन्, अभी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : जो कुछ कहना हो, जल्दी कहिये।

श्री चन्द्र शेखर : तो मैं यह कह रहा था कि अगर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है इस व्यापार के ऊपर, तो उसका केवल एक ही तरीका है कि सरकार पूरी तौर से अपने हाथ में अनाज के व्यापार को ले ले। कोई भी देश, कोई भी हुकूमत, कोई भी राज्य उस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह की धमकी कल व्यापारियों ने दिल्ली में अपनी सभा में दी है।

मुझे हैरानी होती है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में दो लाख मन अनाज कब्जे में किया गया और खाद्य मंत्रालय के लोगों ने कहा कि उन्होंने कमाल किया है, लेकिन तीन दिन के बाद फिर यह कह दिया कि यह वैरिफिकेशन आफ स्टाक है। सरकार को ऐसी ढुलमुल नीति को छोड़ना चाहिये।

अब, श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं दो चार मिनट और लूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। आप इसके लिये मुझे क्षमा करेंगे कि अगर मैं यह कहूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है। आज सवेरे खाद्य मंत्री ने प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने यह कहा कि गल्ला देते समय केन्द्र सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि किसी राज्य की पैदावार क्या है, वहां की आबादी क्या है, वहां की जरूरियात क्या हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के पिछले तीन वर्षों की पैदावार को लें तो ऐसा मालूम होगा कि वहां हर साल पैदावार गिरी है। जहां उत्तर प्रदेश में सन् १९६०-६१ में १४२.५३ लाख टन अनाज पैदा हुआ, वहां सन् १९६१-६२ में १३८.३५ लाख टन हुआ और सन् १९६२-६३ में १३२.७९ लाख टन हुआ और सन् १९६३-६४ में ११६.१८ लाख टन हुआ। इस तरह से उत्तर प्रदेश में आज ४०.३३ लाख टन की कमी है। जब हिन्दुस्तान की सरकार से कहा गया कि उत्तर प्रदेश को गल्ला दो तो पहले जो खाद्य मंत्री थे माननीय स्वर्ण सिंह जी, उन्होंने कुछ वादा किया। पहले से वहां ६८ हजार टन आटा मिलों को और २५ हजार टन बरेली और मेरठ को मिला कर पांच बड़े शहरों को दिया जाता था। इसके अतिरिक्त एक लाख टन प्रदेश सरकार को देने की बात थी। लेकिन अचानक नये खाद्य मंत्री आते हैं और वह कहते हैं कि उनका इस तरह का कोई वायदा नहीं है। फिर कहा गया कि इतना हम पूरा नहीं कर सकते और १ लाख ५ हजार टन सब मिला कर के देने का इन्होंने वायदा किया। बड़ी परेशानियों के बाद कहा कि १ लाख ५ हजार टन के हिसाब से हर महीने में आप को गल्ला भेजा जायगा लेकिन यह गल्ला भी नहीं दिया गया।

मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस बारे में विस्तार से बताऊं लेकिन जून से अगस्त तक उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खिलवाड़ किया गया । उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जून के महीने में सस्ते गल्ले की दूकान खोलीं उनको गल्ला नहीं पहुंचा सकी इसलिये कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जो गल्ला केन्द्र से मिलना चाहिए वह गल्ला उसे नहीं दिया गया । मैं खाद्य मंत्री से जानना चाहूगा कि १ लाख ५ हज़ार टन में से ६० हज़ार टन केवल कबाल टाउंस और दो बड़े शहरों के लिए चाहिए तो बाकी ४५ हज़ार टन में सारे उत्तर प्रदेश की कमी को वह कैसे पूरा करेंगे । पटेल आयोग जिसको केन्द्रीय सरकार ने बनाया उसकी यह रिपोर्ट है कि १९६०–६१ में देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में, केवल चार जिलों में करीब ४ लाख टन अनाज की कमी हुई और १९६२-६३ में हालत और खराब हुई । आज वहां की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि २५ फीसदी नुकसान हुआ—अगर उनकी बात को न भी मानिये तो भी कम से कम २० फीसदी का नुकसान हुआ ही और इस तरह से वहां तीन लाख या साढ़े तीन लाख टन की और कमी हुई है । तो सात या आठ लाख टन अनाज केवल चार पूर्वी जिलों के लिए चाहिए । अब, श्रीमान्, आप ही बताइये ४५ हजार टन महीने में जो यह हुकूमत देती है, उससे क्या होता है । आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है । यह आज का टाइम्स आफ इंडिया है, इस टाइम्स आफ इंडिया में खबर निकली हुई ह कि देहरादून की घाटी में, पहाड़ी इलाकों में, जो हमारी सीमा पर हैं, १४० रु० फी क्विटल चावल बिक रहा है और देहरादून में, शहर में, १२० रु० फी क्विटल बिक रहा है । आज स्टेट्समैन की खबर है कि इलाहबाद शहर में १०५ रु० फी क्विटल गेहूं बिक रहा है । यह उत्तर प्रदेश की हालत है । यह सही है कि फूड मिनिस्ट्री ने जो पैम्पलेट दिया है—मुझे समय होता तो मैं उसको पढ़ता और बताता—उसमें कहा है कि जहां बम्बई में १०४ रु० क्विटल है वहां सहारनपुर में ८७॥ रु० क्विटल है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा है, सितम्बर के महीने में क्या हालत है ।

श्रीमान्, मैं आप को बता दूं कि आज २१ तारीख सितम्बर की हो गई है और २१ तारीख तक १ लाख ५ हजार टन में से कुल ३३ हजार २९३ टन अनाज उत्तर प्रदेश को भेजा गया । मैं इस गवर्नमेंट को इस बात के लिए चार्ज करता हूं कि यह हुकूमत जानबूझ कर के उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है । यह मैं मानता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री को या यहां की हुकूमत में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों को उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बैठे हुए लोगों से कोई नाराजगी है । तो उस नाराजगी को निपटाने का दूसरा रास्ता है लेकिन वहां की गरीब जनता के नाम पर वहां के, उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के नाम पर, वहां के भूखे लोगों के नाम पर मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि यह खिलवाड़ आप न करें । २१ तारीख तक सितम्बर के महीने में, श्रीमान्, कुल ३३ हजार टन अनाज वहां गया है । बरेली के गोदाम को ले लीजिये, एक मन अनाज भी बरेली के गोदाम में नहीं है । अब इन्होंने ५४१ टन भेजा है जो कल तक बरेली नहीं पहुंचा था । आप यह बताइये इन सारी हालतों को देखने के बाद, इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या जवाब है सुब्रह्मण्यम् साहब के पास ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You have put up your case. I hope that the Deputy Minister will consider these things. The Minister will . . .

श्री चन्द्र शेखर : कुल ३३ हजार टन २१ तारीख तक गया है । अगर श्रीमान् चाहें तो मैं बता दूं कि किन किन पोर्टों से कौन से, विज़गापट्टमसे, बम्बई से और कलकत्ता

[श्री चन्द्र शेखर]

से किन किन तारीखों को कितना कितना अनाज भेजा गया । यह हुकूमत एक तरफ यह खिलवाड़ कर रही है दूसरी तरफ जब मैं ने उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों से बात की . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : आपको खत्म करना होगा ।

श्री चन्द्र शेखर : क्या नतीजा है । पूर्वी जिलों के आजमगढ़ के कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कहा कि अगर हमें गेहूं नहीं दे सकते तो हम को सीरा दो, मौलैसेज दो, हम सीरा चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही है, उन के लिए सीरा भेजा जा रहा है । यही नहीं, श्रीमान्, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पंजाब के मुख्य मंत्री से बात की कि ५ हजार टन टूटा चावल—जो जानवरों को खिलाने के काम में आता है वह टूटा हुआ चावल—उत्तर प्रदेश के लिए दिया जाय । रामकृष्ण साहब ने वायदा किया लेकिन फूड मिनिस्टर साहब, सुब्रह्मण्यम् साहब चंडीगढ़ जाते हैं और जा कर कहते हैं कि ५ हजार टन नहीं केवल २ हजार टन जायगा । यही नहीं, माननीय लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर पंजाब की हुकूमत ने २५ हजार टन गेहूं उत्तर प्रदेश को देना मंजूर किया तो सुब्रह्मण्यम् साहब खत लिखते हैं यू० पी० के चीफ मिनिस्टर को कि क्या आपको अधिकार है कि आप सीधे पंजाब के . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I hope that you have taken down these facts, Mr. Shah Nawaz Khan

श्री चन्द्र शेखर . . . मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करें और फिर जा कर के पंजाब के चीफ मिनिस्टर से खत लिखवाते हैं कि २५ हजार टन नहीं केवल २० हजार टन दे सकते हैं और वह भी केन्द्रीय सरकार के द्वारा ।

श्रीमान्, मैं एक अन्तिम बात कह कर समाप्त करूंगा । यह हुकूमत चलती रहेगी लेकिन याद रखें कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते । मैं कांग्रेसी दोस्तों से कहूंगा कि—जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुन कर आये हैं उनसे कहूंगा—याद रखिये कि अगर इन बातों को आप देश के सामने, इन मांगों को पार्लियामेंट के सामने, अपनी सरकार के सामने नहीं रखते तो आने वाले दिनों में क्या हालत होने वाली है यह सोच लें । माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि भुखमरी होगी लेकिन मैंने अपनी आंखों से भूख से तड़पते हुए लोगों को देखा है, भूख से बेहोश होते हुए लोगों को देखा है । मैंने प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को खत लिखा कि इस स्थिति का कोई ठीक हल निकालना चाहिये । कहा गया कि हल निकाला गया है । हल यह है कि श्रीमान्, कोटा आधा किया गया । २ लाख टन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांगा और १ लाख ५ हजार टन दिया गया । अब ९ दिन बाकी हैं और अभी तक कुल ३३ हजार टन ही इस सरकार ने वहां पर भेजा है ।

अन्त में, श्रीमान्, मैं कहूंगा कि जो हुकूमत किसी प्रदेश की, किसी हिस्से की हालत को नहीं जानती, वहां की खूराक की हालत को नहीं जानती उसको हुकूमत में बने रहने का अधिकार नहीं है और खास तौर से मैं श्री सुब्रह्मण्यम् साहब से कहूंगा कि मैं एक किताब को कोट करता लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा, वह किताब है "worldwide wheat planning and economic planning in general" वह इस के प्रिफेस को, पहले पन्ने को, पहले पैराग्राफ को पढ़ लें कि साकेटीज के जमाने में क्या हुआ । प्लैटो का भाई एथेंस का गवर्नर बनने के लिये साकेटीज के पास जाता है और कहता है कि हमारा समर्थन कीजिए । साकेटीज ने पूछा कि एथेन्स में कितने सिपाही हैं, कितनी छावनियां हैं तो उसने कहा कि

उसे ठीक नहीं मालूम । तीन चार सवाल उन्होंने और पूछे । अन्त में उन्होंने पूछा कि एथेंस को खिलाने के लिये कितना अन्न चाहिये, उसने कहा कि उसे नहीं मालूम । तो सार्क्रेटीज ने कहा कि जिस राजा को यह नहीं मालूम कि उसके राज्य में खिलाने के लिये कितना अन्न चाहिए, जिसको वहां की अन्न की समस्या मालूम नहीं उसको हुकूमत में रहने का, उसको स्टेट्समैन कहलाने का कोई अधिकार नहीं । जिस हुकूमत को, जिस वजीर को यह मालूम नहीं कि आज देहरादून की वैली में क्या हालत है, आजमगढ़ में क्या हो रहा है, देवरिया में, बलिया में क्या हो रहा है, उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । आज से तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारे साथ अन्याय किया गया है । तो मैं उत्तर प्रदेश के सदस्यों से खास तौर से और सारे सदन से भी सामान्य रूप से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की इस स्थिति पर विचार करें । कोई भी खाद्य समस्या तब तक ठीक नहीं चल सकती जब तक लोगों की उचित मांगों को पूरा न किया जाय ।

श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि खाद्य मंत्री, मैंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच करेंगे । ये मेरे आरोप नहीं हैं, पिछले साल मैं ने कहा था कि यहां का जो खाद्य मंत्रालय है वह उत्तर प्रदेश के खिलाफ काम करता है । गुड़ आन्दोलन के जमाने में मैंने यह कहा था, उस समय थामस साहब और एक दूसरे वजीर जो अब विदेशी मामलों के वजीर हो गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि किसी हालत में गुड़ के ऊपर से नियंत्रण नहीं हटेगा, मगर उस के ऊपर से नियंत्रण हटा जबकि उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया । इसी तरह इनकी खाद्य नीति तब बदलेगी जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जायगा । धन्यवाद ।

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI (Uttar Pradesh): My hon. friend has made very serious charges against the Food Minister regarding the letter that he wrote . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Ansari, you better raise this question when the Food Minister comes.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: I hope that he will . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): When he replies you can ask for clarification. Mr. Bhuwalka.

श्री रामकुमार भुवालका (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं प्रधान मंत्री श्री शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी स्पीच जो गत शुक्रवार को लोक सभा में हुई उसमें उन्होंने दो घंटे तक स्पीच दी और सारी बातों का खुलासा किया और ऐसी आशा की जाती है कि उन की स्पीच के बाद बहुत सा काम हमारी गवर्नमेंट का सुचारु रूप से चलेगा । दूसरे मैं खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम् साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह मंत्रालय अपने हाथ में लिया और इस भार को संभाला । उन्होंने पहले बहुत खूबी के साथ जो काम लिया था उसे निभाया है । और मेरा ऐसा ख्याल है कि उनका काम ऐसा अच्छा होगा कि थोड़ दिनों के बाद यह जो फूड की तकलीफ है वह हमारे लिए नहीं रहेगी ।

अब मैं अपनी स्पीच पर आता हूं । दो रोज पहले और आज भी मैंने बहुत से माननीय मेम्बरों की स्पीचें सुनीं, कइयों ने कोई ब्लेम लगाया, कुछ क्रिटिसाइज किया, मैं उस तरफ पर नहीं जाता, मेरा काम क्रिटिसाइज करना नहीं है बल्कि मेरा काम यह है कि यह बतायें कि कैसे काम करें जिससे कि हम आगे बढ़ें ।

जब से हमारा देश हमारे हाथ में आया है लोगों की आदतें बदल गई हैं, लोगों की खुराक बढ़ गई है, आदमी बढ़ गये हैं, नाना

[श्री रामकुमार भुवालका]

प्रकार के फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं । फूडग्रेन्स भी हमारा बढ़ा है, पहले जितनी फूडग्रेन्स की उपज होती थी उससे ज्यादा हुई है । मैं कुछ फिगर्स को बताता हूं । १९४८-४९ में हमारे यहां ५१.७५ मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ । १९६१ में ७८.५७ मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ । इसका मतलब हुआ "मोर दैन फिफ्टी परसेन्ट" हमारा प्रोडक्शन बढ़ा । इस पर भी हमारी खाद्य समस्या १९५४ से लेकर अभी तक बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी पापुलेशन भी बढ़ रही है और बिना पापुलेशन को रोके यह खाद्य समस्या बनी रहेगी ।

फिर उसके बाद अभी चार कारखानों को फर्टिलाइजर बनाने के लाइसेन्स दिये गये लेकिन उनमें से एक नहीं बैठा । यह सच बात है कि जब तक खाद के कारखाने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तब तक खाद्य समस्या में सुधार होना मुश्किल है और काश्तकारों को जब अच्छा खाद मिलेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी । इसलिये हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के खयाल से उसके लिये ज्यादा कारखाने बनते और उनकी अच्छी तरह से सप्लाई होती तो अच्छा होता; लेकिन इस के बावजूद, सरकार के बहुत जागरूक होते हुए भी, फूड के मामले में हमारा काम आगे नहीं बढ़ा इसका क्या कारण है इसको हमें सोचना चाहिये ।

हमारे यहां बड़े बड़े लोहे के कारखाने बने । ठीक है, कारखाने बनने चाहियें थे क्योंकि उनकी जरूरत थी । बोकारो में और दूसरी जगहों में लोहे के कारखाने और स्थापित होंगे । लेकिन बिना खाए तो हाथ पैर नहीं चलता । इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि खाने के लिये जिन खाद्य पदार्थों की जरूरत हो उनका पहले प्रबन्ध करें । अभी एक बात चलती है होर्डिंग और हाइडिंग की । होर्डिंग वह कही जाती है जिसमें बैंक से रुपया लिया जाता है, खाद्य के लिये पैसा लिया जाता है । हाइडिंग उसे कहते हैं जिस में प्राइवेट तरीके से छिपा कर माल रखा जाता है । मैं नहीं समझता इस वक्त होर्डिंग कैसे होती है । पब्लिक में माल का आना जाना गाड़ियों में, लारियों में होता है और गोदामों में जाता है । ऐसा कौन हतभागी है जो होर्डिंग करके माल रखे और ज्यादा दाम ले कर बेचे । अगर ऐसा करेंगे तो पकड़े जायेंगे । अभी पटना में बीस गोदाम की चेकिंग में १८०० मन माल निकला । बहुत खोज हमारे देश में हुई कि खाद्य कहां छिपा है । लेकिन मेरे देखने में और सुनने में नहीं आया कि कहीं ऐसा बहुत सा माल मिला हो जिससे अनाज का संकट दूर हो । लेकिन जो भाई व्यापारी लोग इस तरह का काम करते हैं वे देश की सेवा नहीं करते । वे देश का अच्छा नहीं करते और देश के दुश्मन हैं—ऐसा उन को समझना चाहिये ।

फिर उसके बाद किसान के पास जो माल छिपा हुआ है उसको संभालना गवर्नमेंट का काम है क्योंकि किसान के पास साधन हैं कि उसको अपने पास रख सके । कोई व्यापारी छोटी मोटी पाकेट में रखने वाली चीज होती तो रख ली जाती । इसलिये सरकार को बड़े बड़े गोदाम बनाने चाहिये । मेरा खयाल है कि जितनी खोज हुई उस में उतना माल तो नहीं मिला लेकिन अगर और अधिक खोज करने से माल मिले तो कसूरवार आदमियों को पकड़ना चाहिए और सजा भी देनी चाहिये । इसके अलावा हमारा बहुत सा माल अमेरिका से आता है और यहां डिस्ट्रिब्यूट होता है । बम्बई में स्टीमरों के जरिये गेहूं उतारा जाता है लेकिन फिर भी अभाव बना हुआ है । इस का क्या कारण है, क्या वजह है ? इसका कारण हमारी बढ़ती हुई आबादी है । रे पास जो आंकड़े हैं उनको मैं आपके सामने रख कर बताता हूं कि अभी सन् १९६४ खत्म होने वाला है, १९६५ शुरू हो जायेगा । १९६५ और १९७६ में बहुत ज्यादा फर्क

नहीं है । तो १९७६ के आंकड़े मैं आपको बतलाता हूं कि तब तक ६२५ मिलियन हमारी पापुलेशन हो जायगी और १९८१ में हमारी पापुलेशन ६९५ मिलियन हो जायगी और १९९१ में ८३५ मिलियन और सन् २००१ में १५०० मिलियन हो जायगी । ये आंकड़े जोकि हमारे प्लानिंग कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी ने निकाले, इनसे यह मालूम पड़ता है कि हम कहां और किधर जा रहे हैं । जब तक हम जनसंख्या को रोकने का काम अपने हाथ में पूरी तरह से नहीं लेंगे तब तक हमारी खाद्य समस्या कभी हल नहीं होगी, चाहे आप फूड प्रोडक्शन के आंकड़े कितने ही बढ़ाना चाहें । यह कोई खाली फूड की बात नहीं है, मकान की भी समस्या है, कपड़े की भी है और दूसरी चीजों की भी है । जब १९५२ से लेकर अभी तक इतना प्रोडक्शन बढ़ा कर भी स्थिति नहीं संभाल सके हैं तो आगे कैसे होगा ? इसलिए जहां तक संभव हो सके हमें इस जनसंख्या के प्रश्न पर विचार करना चाहिये ।

तीसरी बात है, साधारण स्तर के लोगों को सामान मिलने में और उसके बढ़ते हुए दामों से कितनी तकलीफ होती है इस पर हमें विचार करना है क्योंकि हमारी जो फेयर प्राइस शाप्स हैं उनमें भी माल मिलता नहीं है और दाम ज्यादा देने पड़ते हैं । तो आखिर क्या कारण है, माल कहां जाता है ? आज मैंने स्टेट्समैन अखबार में पढ़ा कि यहां दिल्ली से पांच पांच किलो कर के माल बाहर जाता है । यहां के चीफ कमिश्नर ने खुद देखा और उन की समझ में आया कि इस तरह से कितना माल जाता है । जब दिल्ली में ऐसी अवस्था है तब सारे देश में कैसे पकड़ हो सकती है यह देखने की बात है । सैकड़ों की तादाद में पांच पांच किलो माल बड़ी बोरियों में बंद कर के यू० पी० की तरफ ले जाया जा रहा है ।

इन सब बातों को देखते हुए मैं गवर्नमेंट से और फूड मिनिस्टर से अपील करूंगा कि वे खाद्य की परिस्थिति पर पूरा ध्यान रखें ।

SHHI UMASHANKAR D1KSHI.T CUttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, we have discussed the most important aspects of the problem of food and agriculture during the debat* that has gone on, and I find that certain basic issues have become clear. We have to realise that agricultural production is governed to a material l extent by the condition of the mon-J soon, by rain by whether there is excess rain or short rain or normal supply of rain. This fact has to be realised for understanding the situation. If we go back and try tp study the history of food production during the last few years or even the last j half century. w_e will find that j whenever rains have failed, whenever j there has been exceedingly short sup-] ply of rain, or there have been large I tracts inundated by floods, in the lat-j ter case the damage and harm are not l so grave as in the former case. How-j ever, under all circumstances we have ! to accept the fact that if the monsoon ; goes against us, if there is a serious I drought, no matter what action you I take, it is not posible to avoid famine I and conditions of shortage in the j country. That fact has to be realised. i

The other fact which comes out from ; the excellent booklet which the Food Ministry has published giving a review of the food situation is that whereas in the former times a few large producers or traders hoarded grains in large quantities, now as a result of a consciousness that has come about among producers, small, minor or large, there is a tendency among them to hold stocks at tht. time of harvesting. The result is that whatever the surplus rice or wheat or other grains in the country, it is spread all over the country in hundreds and thousands of small godowns which it is not easy to locate and seize. If any large accumulation of stocks can be detected and pointed out to the Ministries, I have no doubt that both the Central and the State Governments will track down the hoarders and seize the excess stocks;

[Shri Umashankar Dikshit.] but the whole difficulty of the situation is that hoarding has taken place over. a large number of places by a large number of, people in small quantities comparatively.

The third fact which is more or less beyond control is the excess spending caused by the Chinese attack. It is the annual expenditure of over Rs.500 crores additionally, which throws a large, amount of currency into the country in the hands of the people, which naturally raises the prices, not only of foodgrains but of all commodities. The general level of prices has been arising. That fact has also to be accepted. We have to live, as Mr. Mishra said, with the preparations for defence over a long period. Therefore if we see these three main factors in a balanced, cool and reasonable frame of mind and try to understand the situation, we will find that this is not something of which conscientiously or honestly political advantage can be taken. I am afraid I have seen some sort of political approach being injected into the discussions not only by the Members of the Opposition but by our own Members of the Congress Party. Somehow we are unable to resist the temptation to point out a defect against the Government when we think we can easily point it out. It is really far too serious a matter. Mr. Anna-durai was complaining that this appeal for politics not being imported into the food matter is not very correct for the Government and for the Congress side to do, because the Congress people themselves were importing politics into it and he mentioned one or two instances. I do not think some isolated matter like that can t?o to prove that the Congress or the ruling party or the Government are consciously or to any appreciable extent at all allowing political considerations to influence them in the consideration of the food problem. That is not a correct position. In any case, it is not in order to get some particular advantage out of the appeal that the appeal is made because it is a matter of national emergency or grave national interest. My impression, after hearing Mr. Subraman-iam's speech and reading that excellent booklet, is that he has acquired a great grip, a considerable grip over the situation. He has understood the situation well, he has analysed the factors which have contributed to the present situation and he has produced a plan and a programme for meeting them both on a short-range, immediate range and on a long-range basis. So far as the long-range plan is concerned, I do not really have much to say because I believe that he has gone into great details about it and if these measures are implemented seriously, consistently and thoroughly, I, have no doubt that better results will be obtained. I am more worried about the immediate situation.

I entirely agree with my friend, Mr. Chandra Shekhar, that the situation is exceedingly serious. At any rate, so far as U. P. is concerned, I can say with knowledge— I have just *come* back this morning—that the condition, in all conscience, is exceedingly difficult. I have received information from the U. P. Government offices here in Delhi to tell me the position and that up to the 20th, i.e. if you exclude the last two or three days, the total supply i_s only a little over 33,000 tons. There also we do not know how much has arrived because this information that has been received by the U. P. Government is of despatches from the ports, despatches up to the 17th, 18th and 20th. We do not know how much had actually arrived in the State. I do not know whether there is a misunderstanding of the situation, or what is responsible for it, but a serious situation is being allowed to develop from day to day and proper measures are not taken. I can fully understand that this may not be really due to any lack of care on the part of the Food Ministry. Possibly orders have issued. I have personally no doubt

that they must have been issued but j what has happened up to 18th September?

THE DEPUTY MINISTER *m* THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI D. R. CHAVAN) : About 40,000 tons of wheat and other grains have already reached them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. 1 BHARGAVA) : That is not the U. P. \ Government's information, I am afraid.

SHRI D. R. CHAVAN: Thiis is my information.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: That is, they have been despatched?

SHRI D. R. CHAVAN: That has reached U.P.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: I only two hours back got a telephone message. I do not know how this discrepancy can arise . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. ' 3HARGAVA>: GO ahead.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: I would request the Minister to establish contact and to settle this kind of small misunderstandings because the matter is far too serious for a cavalier or casual treatment. It is wrong to think that it is one particular State which is concerned. It is likely that this will have tremendous repurcussions all over the country. Admittedly the Maharsshtra State has got 100,000 tons. I do not want to draw any distinction or any invidious distinction in regard to Bombay City having separate arrangements. Eombay city is a city of 40 lakhs and that means equal to all the KAVAL towns of U.P. or more. But a State like U.P. with double the population is getting not even 100,000 tons. What can you do? After all you cannot fly the supplies by aeroplanes. Even if 40,000 tons have been already sent, I want to know how in the "-'lext nine days, the Deputy Minist .' can complete the quota of 105,000 tons. Anyway this matter has to be gone into. I went to a village and there two women and an old man got hold of my feet crying and they said: 'You get me a card because we have not had any food for three days'. On these matters, why we are not able to carry conviction to the Minister and to others about the seriousness of the situation really passes my comprehension. But, Mr. 2 P.M. Vice-Chairman, you are well aware that Congress Members of Parliament from Uttar Pradesh— and I think others also—met under the chairmanship of Mrs. Indira Gandhi and the matter was taken to the Minister, and I think it was also considered by the Cabinet. I do not know what the exact outcome of it was, but I do want to lay the utmost emphasis on the need, on the urgent immediate need for augmenting the supplies and making additional arrangements for transport. I was saying— when I interrupted myself—that, may be that orders for sending adequate supplies from the ports have been issued but something might have gone wrong on, the railways. Well, I think something like a control room should be established where from hour to hour reports should be received, orders should be issued to ensure that at least the allocated supplies are sent out from the ports. If the railway system is unable to cope with the volume of supplies necessary, then there is no reason why Government should not use all the facilities available by road transport. After all private vehicles and even Government vehicles can be commandeered and foodgrains can be rushed to the shortage areas, and it should be done as quickly as possible. This is so far as the immediate thing is concerned.

I will not take long, Sir, but I will briefly refer to the long-range programme which the Minister has carefully evolved. I say that the Minister really deserves congratulations on the manner in which he has gone into great detail and has tried to evolve an integrated plan. I do not say it is a

[Shri Umashankar Dikshit.] paper plan; I say it is a very serious 1 and well-conceived plan. But very ! much depends upon its implementation. It is not in Mr. Subramaniam's hands, however able he is; I know he is able and I hold him in very high regard for his ability and for his understanding of the problems. But it is not in his hands—the implementation part of it. It is not as if it is a large farm which Mr. Subra-maniam or other Ministers will just go and supervise and get the farmers to produce the required quantity of food. They are spread all over the country, small and large farms, hundreds of thousands of farms, for which there are the State Governments and the other small territorial Governments responsible, and there js also the lag of centuries of local conservatism which is coming in the way. Now therefore it is the implementation which will really matter.

So far as U.P. is concerned, I want to point two or three difficulties or deficiencies which we have noticed. Now the most important thing for any programme of food production or agricultural production to succeed is that it must have adequae irrigation; it should have adequate irrigational water supplies. One great problem that I have seen is that while a particular area is supposed to be served by a canal system or by a tubewell * system, the position is very unsatisfactory in most cases, because the command area attached to a tubewell or to a local canal system is usually very much more than really justified by the water supply actually available. It is either because there are local pressures from the farmers as from the people where you have a new tubewell, and then everybody comes up and says: "Include my field in the command area." It is wrong to allow this sort of thing to happen because, while the Government may feel satisfied that so much area is covered by tubewells or by the canal system, actually, at least 25 per cent of it is not fully supplied. Of course the recent reorientation or change in emphasis from large irrigation to« minor irrigation is really a step in the right direction—and I find that in some of the districts good work is being done—and I hope it will be continued, but some sort of a probe has to be done, enquiry has to be made to find out whether the total area attached to, say, the Sharda canal system, or any other canal or local irrigation system, is really not in excess of the supply provided by-it.

THE VCCE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARCAVA): Yes, it is time to finish.

SHRI UHASHANKAR DIKSHIT: I think I will conclude my remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P: BHARGAVA) : Thank you. Ten minutes; Mr. Damodaran.

SHRI K. DAMODARAN (Kerala): Sir, I support the proposal made by the Food Minister to set up a State' Foodgrains Trading Corporation.

It is true that it is very difficult to pass judgment on the scheme which is not yet born, especially because the Minister has not yet explained the precise nature of the Corporation,, its composition, its functions, how far its operations will extend, how couretely it will help us to surmount, the food crisis and assure food to the people at reasonable prices. But he has proposed that the Corporation should have the monopoly of the movement of foodgrains through rail-ways. And secondly he has proposed, that this Corporation should have the powers to acquire foodgrains from the private dealers. I welcome these proposals because I believe that the proposed Corporation should have a commanding position, a strategic position in food, and not become just another trading agency to compete with the existing ones. The Corporation will succeed only if the entira wholesale trade, at least a lion's share of the wholesale trade, is taken over by this Corporation, and only retail

trading is left to the whims and fancies of the competitive field, and that too under strict control.

The Food Minister's review of the :food problem and his proposed measures to solve the problem show that he is aware of the gravity of the situation, and also that he is earnest ' in tackling it. I hope he will muster enough courage and determination to implement his proposals. I say this because, *ae* everybody should know, the private trader is a powerful force, more clever, more shrewd, than any Food Minister, however sincere he may be.

We have seen how in April this •year the foodgrain dealers threatened a countrywide strike to force the Government to withdraw or modify the Foodgrain Dealers Licensing Order to their satisfaction. And what happened? The Government, with all the forces at its command, -with the Essential Commodities Act and the all-powerful Defence of India Rules in its pocket, went down on its knees to negotiate and compromise with the private traders. Such is the power of the trader, the hoarder, the speculator. These elements are not only unscrupulous but inhuman, and they will resort to any means to increase their own profits. Of course the Government has repeatedly declared that the private traders have not behaved properly, they withhold stocks from the market, they create artificial scarcity, and they increase the prices, but the Government has been helplessly watching the situation. Of course, they go on issuing pious and harmless appeals, advices, warnings and graces. But the private trader treats them, naturally, with cor.tempt and goes on increasing the prices. These forces, I am afraid, will certainly try to see that the preseni Food Minister fails in his attempt, that either he surrenders to them or he goes into oblivion as many others have gone. I hope the Food Minister wil be vigilant. What is necessary at *t:.t* n..)».. it is that the Government should assure itself that the next harvest is not cornered by the private wholesaler. Time is the most decisive factor.

Sir, as the Food Minister himself has stated, the problem of food cannot be solved merely from the distribution point of view. As he has stated, distribution is inseparably connected with production and you cannot tackle the problem of production unless the basic problem of land reform is tackled properly. Without security of tenure, without the conferment of ownership on tha cultivating tenant, with evictions and exploitation rampant in the countryside, the peasants will not be inspired to produce more. My hon. friend, Shri Dahyabhai Patel, created some stir in the House the other day by showing us a copy of an authoritative book on land reforms in Taiwan written by one Mr. Chen Chang, a high official of the Taiwan Government. Mr. Patel was kind enough to lend me the book for one night and I went through it. Although I do not agree with some of the conclusions and formulations made in the book, I am glad to find myself in agreement with Mr. Patel in appreciating many of the land reform measures adopted and implemented by the Chiang Kai-shek Government in Taiwan. On the very first page of the book you find the following statement. I am quoting:

> "The feudal form of land distribution was unjust and objectionable. Unrestricted appropriation of land for their own benefit by big landlords must be considered outrageous."

This is a statement that every leader of the Swatantra Party should learn by heart, especially as it comes from Taiwan. I am tempted to quote another paragraph from the book. Mr. Chen writes:

> "In tilling land that does not belong to him, the tiller feels no special love for the soil and has

I Shri K. Damodaran.J little interest in increased production. From the viewpoint of the national economy such a state of affairs is a great loss. Not only that, but the tenant farmer has to live in misery in spite of the yearlong efforts he has made in the fields, while the landlords could live comfortably without working. This contrast could have created serious conflict between classes. If this situation had remained uncorrected, it could have been a source of social and political trouble."

That is very similar to our own conditions. But they have now changed those conditions by adopting drastic measures and I am glad to see that the Swatantra Party Leader has praise for them. What were those measures? A ceiling was introduced , and no landlord was allowed to retain more than 7 acres of land, not more than 7.1 acres of land, to be exact. All the remaining land was compul-sorily taken over by the State and sold to the actual tillers at reasonable prices. Of course, some compensation was given, but it was far less than what we give to our landlords here. It was only two and a half times the annual harvest, that is to say, six or seven times the annual rent that the landlord used to receive. Even that small compensation was not paid to him in cash, because they thought that cash payment would result in inflation. So 70 per cent, of the compensation was paid in land bonds in kind, and 30 per cent, with stock shares in government enterprises. The price of the land was to be paid in twenty equal easy instalments over a period of 10 years. The | first instalment began in 1953 and rfcw ' the law has been completely imple- ' mented and the actual tUlers aro in ' possession of the land. The peasant* were also encouraged to produce more with all sorts of government help, financial and otherwise. They werp also encouraged to operate their farms with modern techniques on a cooperative basis. What was the : result? The result was that they have increased their food production to a considerable extent.

All this is very good and it is good that the Swatantra leader supports it. What I don't understand is only this. According to the Swatantra party, cooperative farming in Taiwan is pure democracy, but in India it is no'.hing but communism. Ceilings and retention limits to landlords" property in Taiwan are good, but ceiling in India is undiluted totalitarianism. I cannot understand this. (Time be!l *rings.)* Is my time up?

THE VICE-CHAIRMAN (SHHI M. P. BHARGAVA) : Yes, you finish now. Try to wind up quickly.

SHRI K. DAMODARAN: I hav* only just begun.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Well, your associates took some of the time.

SHRI K. DAMODARAN: Mr. Bhupesh Gupta took 30 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : No, no. There were others also. You conclude please.

SHRI K. DAMODARAN: I cannot understand this mentality of the Swatantra Party leaders. They praise land reforms in other countries; but they don't see that similar reforms, abolition of all remnants of feudalism and conferment of land to the tiller, and encouragement given to the actual tillers, all these are necessary in our country also. We are suffering today and there is the food crisis because the Government has failed to implement land reforms even the reforms passed by the State legislatures.

Sir, the prob'em of prices of food-grains cannot be isolated from the problem of the maintenance of the general price line, in other words, from the inflationary forces which

are now threatening our entir<: economy. The root cause of inflation is, as everybody knows, that the increase in our money supply has no relation with the increase in production of commodities. It is said that in the las. three years the money supply has risen by 31 per cent, whi.'.e the real production has increased only by 8 per cent. Many have blamed the deficit financing that has been resorted to by the Government and said that that is the villain of the piece. It has been pointed out that although the Third Five Yea$_r$ Plan target for deficit financing was only j Rs. 550 crores, only during the last three years over Rs. 600 crores of deficit financing was resorted, to. From this again, the demand is made that the order of priorities in our Plan should be changed, that the priority given to heavy industries should stop, and that the first priority should be given to agriculture, the second to roads etc. the third to consumer industries, and only the last to heavy industries. This is a demand first put forward by the Western imperialists with a view to keeping our country backward, to make our industries dependent on machinery imported from the West, to make our strugglj for I economic independence a mockery. India has rejected this demand. But we can change our policies, enunciated by the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and accepted by the country in general, only at our own peril. If anybody thinks in the name of deviationism, in the name of the right of a great m;vn to deviate from the beaten track, in the name of becoming original, he can abandon the legacies left by the late lamented Premier, he is sorely mistaken. Not the positive Nehru 1radi-tions and the path shown by Nehru, but the leader who throws those traditions into cold storage, will be abandoned by the country and the people.

It is true that there is a lot of | wasteful expenditure. All wasteful, | unproductive expenditure should be I reduced drastically, and to that extent, deficit financing by the Government can be reduced. But to say that investment in heavy industry has caused inflation is a bogus theory.

Money supply has increased considerably no doubt. But money suppiy means not only the currency notes created by the Reserve Bank. It also includes the money created by the private sector with the help of the banking system, and the current deposits as well as time deposits of the private commercial banks also contribute to a rise in prices and a depreciation of our rupee. In the first three years of the Plan, the net" bank credit created by the privat? sector amounted to Rs. 414 crores. This i» the deficit financing resorted to by the private sector.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Damodaran, I am. afraid you will have to wind up now. Mr. Gupta has taken 38 minutes.

SHRI K. DAMODARAN: But this deficit financing by the private sector is never mentioned in our discussions. What I want to say is that this private sector should not be allowed to have i.s own way.

If prices of all industrial products are allowed to increase then a redue-ton in respect of agricultural products alone will not be possible and that Is why the maintenance and stabilisation of the general price line has become necessary but this can be achieved only by a bold pohcy of nationalisation of banks and some important industries like cement, etc., in such a way that the public sector becomes dominant and the Government is able to control th~ market in the interests of the people. This is 1he only way; there is no other way because economic laws are more powerful than the most powerful State in the world.

SHRI R. P. N. SINHA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, I would like, at the very outset, to congratulate the'

[Shri R. P. N. Sinha] hon. Food Minister for the excellent manner in which he has tried to tackle the food problem. Ic is very significant that while in Bengal, during the early forties, two lakhs of people died of starvation there has not been a single starvation death in the country during the rjresent food crisis. This goes to his credit. I do not consider this'food problem to be an unsurmountable one. If the sieps that are being taken are taken with a .strong hand I am sure this problem can be tackled. It is an old saying that desperate diseases by desperate methods are cured and I am sure the hon. Food Minister will not shirk taking strong measures wherever necessary in the course of finding a solution to this problem. Merely fining a few persons a few hundred or thousand rupees or by sending a guilty person to prison for three months will not do. You have got to take stringent measures as they did to put a stop to profiteering in foodgrains in China. We may have many things against China but that was an action which promptly put a stop to profiteering in foodgrains. 1 hope the hon. Food Minister is quita alive to that situation. The present, food shortage has been due to hoarding. Now, hoarding is there, and I suppose it is known to the hon. Minister, at three sectors. The first is by the growers. I come from a village and I know that there are people, growers who have still thousands of maunds of foodgrains hoarded in their godowns. The first hoarding has been done by the growers, secondly by the traders and thirdly. due to the panic created by rhe Opposition parties, newspapers and mch others, by the consumers. Thinking that it may be impossible in the future to secure food many of the consumers have bought foodgrains »nd have hoarded them; it may not be on a large scale but it is there. Now, if the hoarded grains are brought out, they, along with the foreign imports, I am sure, will over-come the present shortage especially with the coming in of the new crop of paddy in a month or so hence. As the hon. Prime Minister said in Calcutta it will not then be difficult to solve the problem and the situation is bound to improve within a short time.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

At the same time, I am sure I am not unmindful of the fact that even though the food situation is bound 10 improve, prices will not come down to as much as they were a year back. The price line is bound to remain at a higher level. I need not reiterate what so imany Ihon. Members have said about the price-line having gone up. It is bound to.go up with all the Plans that we are putting into operation; these could not but lead to in-flation. Now, this inflation, although it has created some sort of inconvenience to the people, is bound to be there at least for eight years to come. If India is to turn into a developed country, this inflation has got to be put up with. It is a sort of birth-pang which one has got to tolerate or suffer from for some time to come until all the investments that have been put in the schemes and Plans start giving returns and production from the factories begun coming in. Therefore, it would be absolutely incorrect t_0 think that with all the efforts that Government are making the prices of foodgrains, as of other essential commodities—because they are, all of them, inter-related, obviously—will com$_e$ down to a very low level.

Now, it is no good going into the details of the prices, the per capita requirement, availability of foodgrains and so on and so forth. A lady Member in the other House said that the food available *per capita* per day, was one lb. at the same time, Dr. Lohia said that it was only a few ounces. Now, it is no good going into these details because I must confess that, like our Father of the Nation, Mahatmaii. I do not believe in these figures. I know how these figures are obtained. I come from the villages

and these figures that are obtained through the village chowkidars are more imaginative than real and, therefore, all these figures, statistics, that are there are, I am sorry to say, unreal and not much reliance can be placed upon them.

As I said earlier, Madam, I do not consider the food problem as it exists today to be an insoluble one. With the efforts that the hon. Food Minister is putting in, the situation is bound to improve in a month's time, especially with the coming in of the new crop. Nevertheless, I do feel unhappy that the present food crisis has to be tided over with the help of food imports from outside. How long shall we depend upo$_n$ these imports? Herculean efforts have to be made io increase food production. Unfortunately so far, no proper efforts have been made in that direction. The Planning Commission gave first priority to land reforms about which an hon. friend just now spoke, with a view to increasing food production but instead of increasing food production, it had an adverse effect. Imposition of land ceilings has retarded rather than helped increase production inasmuch as investment on land to help increase production has come down to Ihe lowest level and rightly so, Why should anybody buy a tractor costing twenty thousand rupees or invest six to eight thousand rupees on tube wells for the cultivation of twenty or thirty acres? This land ceiling business was tried in America and a ceiling of one hundred and forty acres was put. This was afterwards found to be unjustified for the required investment on cultivation and, therefore, the ceiling had to be raised and it was raised from one hundred and forty acres to three hundred acres. Here too. we should have taken lesson from the American experiment. That we unfortunately halve not done. If, however, it is considered impossible to go back upon this ceiling business, Government should at least try to offer sufficient incentives for co-operative farming and make resources available to the cultivator at sufficient cheap rates. It is sad reflection that whereas we have invested crores and crores over ....

:

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Would you please wind up?

SHRI R. P. N. SINHA: I will wind up in a minute.

Now, it is a sad reflection that we have invested orores and crores in steel and other factories but we have not put up even a single factory for the production of small tractors. The tractors that are assembled here tost a lot and you cannot expect a farmer who owns 20 acres of land to go in for these costly big tradtors. It is therefore necessary that the Govern ment should put up at least one factory to produce small tractors like those Russian tractors which could be bought for few thousand rupees and in which the small farmers—after the ceiling has been imposed I do not suppose there will be any big farmers left—could Comfortably invest. Therefore I hope the Government will consider this question.

Before I end I would strongly urge the Government to make tremendous efforts to ensure greater output of foodgrains in the years to come and not rest on their oars after having been able to solve the present food crisis. And in that effort of theirs I wish them God Speed. Thank you.

ALLOTMENT OF TIME FOR GOV-ERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting hefld today has recommended allocation of time for Government and other Business as follows: —